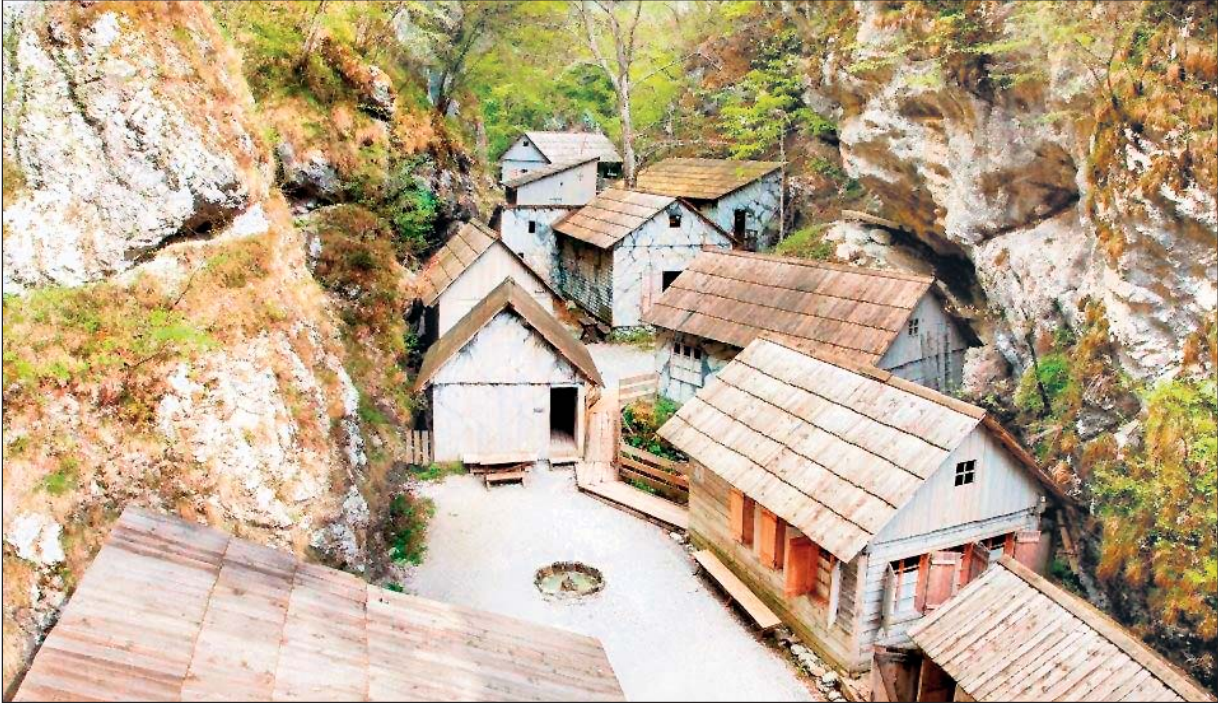




दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान जब स्लोवेनिया पर नाज़ियों का कब्ज़ा था तब देश के “प्रतिरोधी आंदोलन” (रैजिस्टेंस मूवमेंट) ने घायलों की देखभाल के लिए घने जंगलों में, गुफाओं, संकड़े पहाड़ी दर्राँ जैसी जगहों पर गुप्त अस्पताल बनाए, ताकि वे शत्रु की पहुंच से बचे रहें क्योंकि नाज़ी अक्सर अस्पतालों को नष्ट कर देते थे। इन अस्पतालों तक पहुँचना ही बहुत मुश्किल होता था। वर्ष 1942 से 1945 के बीच स्लोवेनिया में ऐसे 120 अस्पताल थे, जिनमें अलग-अलग देशों के 15,000 से ज्यादा घायलों व बीमारों को शरण मिली थी। ये सभी सैनिक तब फासीवाद और नाज़ीवाद से लड़ रहे थे और इनका अस्तित्व स्थानीय लोगों की सहायता पर निर्भर होता था। स्थानीय लोग इन्हें भोजन पानी देते थे व घायलों को अस्पताल पहुँचाते थे। यही नहीं, इन अस्पतालों की देखभाल भी स्थानीय लोग ही करते थे। इसके लिए लोग प्रायः अपनी सुरक्षा को भी खतरे में डाल देते थे। उस समय बने गुप्त अस्पतालों में से कुछ आज भी मौजूद हैं। हालाँकि अब वहां इलाज नहीं होता है। इन्हीं में से एक है, चित्र में नजर आ रहा, फ्रान्चा पार्टिसन हॉस्पिटल, जो वैस्टर्न स्लोवेनिया में है। उस समय यह एक सर्वाधिक सुविधा सम्पन्न अस्पताल था। यहां एक्सरे मशीन, ऑपरेशन थिएटर आदि, सब कुछ था। यह अस्पताल जर्मन अधिकृत यूरोप में एक दर्रे में बनाया गया था। इस क्षेत्र में जर्मन सेना की आवाजाही काफी थी पर यह अस्पताल गुप्त ही रहा। अस्पताल का दरवाजा छुपा हुआ था। “रीट्रैक्टेबल” पुलों के जरिए ही इस अस्पताल तक पहुंचा जा सकता था। ये वो पुल थे जिन्हें जरूरत पड़ने पर हटा दिया जाता था। अस्पताल की गोपनीयता कायम रखने के लिए मरीजों को आँखों पर पट्टी बांध के लाया ले जाया जाता था। यह अस्पताल 1943 में स्थानीय डॉ. विक्टर वोल्कजैक की देखरेख में बना था पर इसका नामकरण डॉ. फ्रान्चा बॉज्क के नाम पर किया गया, जिन्होंने 1944 में यहां डॉक्टर व हॉस्पिटल मैनेजर की हैसियत से काम किया था। अस्पताल में 120 मरीज रखने की क्षमता थी पर युद्ध के दौरान इससे दस गुने मरीज यहां रहते थे। यहां एक जर्मन सैनिक का भी इलाज हुआ था जो ठीक होने के बाद यहीं रह गया और मरीजों की सेवा करने लगा। युद्ध के बाद इस अस्पताल को म्यूज़ियम में बदल दिया गया और आज भी यह स्लोवेनिया का ऐसा स्मारक है जहां सबसे ज्यादा लोग आते हैं।

सब तरह से घिरी ममता बनर्जी, मां दुर्गा की शरण में पहुंचीं

दुर्गा पूजा उत्सव के आयोजन के लिए दो सौ करोड़ का अनुदान दिया। हैलिकॉप्टर उपलब्ध कराये, व ग्यारह दिन की सरकारी छुट्टी दी

—अंजन रॉय—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 22 अगस्ता। इससे ज्यादा सनकीपन और क्या हो सकता है! पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा उत्सव मनाने के लिये बहुत बड़े पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के अन्तर्गत, स्थानीय संगठनों को 200 करोड़ रुपये दिये जायेंगे ताकि वे अपनी-अपनी बस्तियों में दुर्गा-पूजा उत्सवों का आयोजन कर सकें। राजा-महाराजाओं एवं रानी-महारानियों की तरह, ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि लोगों को राज्य में वर्ष में एक बार होने वाले दुर्गा-पूजा महोत्सव को ग्यारह दिन तक आनन्द पूर्वक मनाना चाहिये। इसके सरकार लोगों को कार्यस्थल से गैरहाज़िर रहने तथा मौज-मस्ती करने की छुट देगी। सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि यह सब कुछ उस स्थिति में किया जा रहा है, जब राज्य सरकार सरकारी तथा व्यवहारिक तौर पर दिवालिया होने की स्थिति में पहुँच चुकी हैं।

शिव सेना कश्मीरी दलों के पक्ष में

—श्रीनंद झा—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 22 अगस्ता। कश्मीरी की राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को सोमवार को एक अप्रत्याशित क्षेत्र से समर्थन मिला। शिव सेना कश्मीर में रह रहे गैर कश्मीरियों को मताधिकार देने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ कश्मीरी पार्टियों के विरोध प्रदर्शन को सही ठहराया था। समर्थन मिला। चुनाव आयोग के प्रस्ताव के खिलाफ किए जा रहे उनके विरोध का शिवसेना ने समर्थन किया है। चुनाव आयोग के प्रस्ताव के अनुसार जम्मू तथा (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- यह “तोहफे” उस समय दिये जबकि, प.बंगाल सरकार अपने आप को कई बार ऑफिशियली दिवालिया बता चुकी है।
- एक उल्लेखनीय बात यह भी है कि, ग्यारह दिन के सवैतनिक अवकाश का सरकारी कर्मचारी व कॉरपोरेट दुनिया के “ऑर्गनाइज़्ड” वर्कर तो आनन्द लेते हैं, पर, समाज का सबसे कमजोर वर्ग, दैनिक मजदूरी से पेट पालने वाला, भूखों मरने के करीब आ जाता है, क्योंकि सार्वजनिक सेवाएं व सुविधाएं बंद हो जाती हैं। अतः ये सब लोग कमाई से वंचित हो जाते हैं।

राज्य का खजाना खाली है तथा मुख्यमंत्री ने पूजा-समारोह-आयोजकों के साथ एक विशाल सम्मिलन में इस बात को स्वीकार किया था। लेकिन उन्होंने उस समय यह आशा भी व्यक्त की थी कि माँ दुर्गा राज्य के खजाने को भर देंगी। आशा की जानी चाहिये कि देवी दुर्गा ममता बनर्जी की प्रार्थना सुनेंगी तथा अपनी पुत्री, माँ लक्ष्मी को आदेश देंगी कि वे पश्चिम बंगाल सरकार के खजाने

आर्थिक योजना विकसित करने की कोशिश करने के बजाय, मुख्यमंत्री ऐसी पवित्र आशाएं सँजी रही हैं कि उनकी गैर जिम्मेदाराना व्यव की योजनाएं कुछ-कुछ पूरी हो चुकी हैं। पूजा समारोह आयोजित करने वाले स्थानीय क्लबों के लिये ऐसी उदार घोषणा करने के साथ ही, सुश्री बनर्जी ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिये लम्बी छुट्टियों की घोषणा भी कर दी है। राज्य कर्मचारियों इन समारोहों के लिये लगातार 11 दिन का सवैतनिक अवकाश मिलेगा। उन्होंने जनता से कहा है कि वे इस पर्व का खूब आनन्द लें। दुर्भाग्य की बात यह है कि वे यह महसूस नहीं कर रहीं कि प्रत्येक सार्वजनिक अवकाश का मतलब यह भी होता है कि आप समाज के सबसे कमजोर वर्गों के लोगों को दैनिक मजदूरी से दो रोटी कमाने के अवसर से वंचित कर रहे हैं। इन जबरदस्ती दी जा रही छुट्टियों से बहुत अत्यावश्यक गतिविधियाँ भी मजबूर बन्द रहेंगी, जो (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- सुप्रीम कोर्ट ने खेलों में सरकारी दखल को रोकने के लिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन पर नैशनल स्पोर्ट्स कोड के तहत गठित कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स पर रोक लगा दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस कोड के अधीन दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त तीन सदस्यीय कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स (सी.ओ.ए.) को इण्डियन ओलॉम्पिक एसोसिएशन (आई.ओ.ए.) का कामकाज संभालने से सोमवार को रोक दिया। जस्टिस डी.वाय. चन्द्रचूड और जस्टिस ए.एस. बोपन्ना की एक सुप्रीम कोर्ट बेंच ने 28 अगस्त से शुरू होने जा रहे ए.आई.एफ.एफ. के चुनाव कार्यक्रम (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आओ। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आपके खिलाफ सी.बी.आई. और ई.डी. द्वारा लगाए गए सभी केस बंद हो जाएँ।” सी.बी.आई. ने आप पार्टी के सीनियर नेता पर दिल्ली की आबकारी नीति में बदली गई कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार से संबंधित एक केस को लेकर हाल में छापा मारा था। आबकारी नीति को इस वर्ष की शुरुआत में लागू किया गया था और फिर वापस ले लिया गया। प्रकट रूप से अवचलित, सिसोदिया ने गत सप्ताह यह कहकर बात को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया कि दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 अपने आप में सर्वश्रेष्ठ थी और यदि पूर्व

—लक्ष्मण वेंकेट कुची—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 22 अगस्ता। भाजपा इस समय दक्षिण भारत में जबरदस्त मेहनत कर रही है। अब इसने पूरा ध्यान दो तेलुगुभाषी राज्यों-तेलंगाना और आन्ध्र प्रदेश पर लगा दिया है पार्टी के अपने शीर्ष नेताओं को अपने अनुकूल वातावरण बनाने के अभियान में लगा दिया है। इन दोनों राज्यों से 42 लोकसभा सांसद चुने जाते हैं, इसलिये भाजपा के दक्षिण भारत सम्बन्धी योजनाओं में इन दोनों राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पिछली बार चार लोकसभा जीतने के बाद, जहाँ तेलंगाना में भाजपा अपनी मौजूदगी के विस्तार वास्तविक सम्भावना देखती है, वहीं आन्ध्र प्रदेश में, पार्टी अपने विस्तार के लिये गंभीर कोशिशें करना शुरू कर दिया है। ज्ञातव्य है कि तेलंगाना विधानसभा में भी भाजपा की दो सीटें हैं। इस सन्दर्भ में, पूर्व भाजपा अध्यक्ष तथा केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह एक रोचक व्यक्ति जूनियर एन.टी.आर. से मिले। जूनियर एन.टी.आर. अपने समय की प्रख्यात फिल्मी और उसके बाद राजनैतिक हस्ती रहे एन.टी.रामाराव के पौत्र तथा नामी फिल्म स्टार हैं। ज्ञातव्य

- आंध्र के पूर्व मु.मंत्री एन.टी.आर. जिन्होंने तेलुगू-देशाम पार्टी बनाकर, आंध्र से कांग्रेस का सफाया किया, तथा कई बार लगातार आंध्र के मु.मंत्री बने, के पोते एन.टी.आर. जूनियर, जो स्वयं भी ठीक-ठाक फिल्म अभिनेता हैं, के अब भाजपा से जुड़ने की भारी चर्चा है।
- जैसा कि विदित ही है, तेलुगु भाषी तेलंगाना व आंध्र में, सदा से फिल्म अभिनेताओं के लिये जनता में भारी आकर्षण रहा है। भाजपा अब एन.टी.आर. जूनियर को जोड़ कर, इस “फिल्मी क्रेज़” का लाभ लेना चाहती है।

है कि टी.डी.पी. के संस्थापक एन.टी.रामाराव ही थे। हैदराबाद में डिनर पर हुई इस उल्लेखनीय भेंट ने राजनैतिक हल्कों को आशाओं-अपेक्षाओं से पूरी तरह भर दिया है। प्रसंगवश बता दे कि फिल्मों के दिवाने रहे एकीकृत आन्ध्रप्रदेश में, एन.टी.आर. ने अपनी पार्टी बनाई और पार्टी की स्थापना के नौ माह के अन्दर ही सुस्थापित कांग्रेस पार्टी को उसके गढ़ रहे आन्ध्र प्रदेश की सत्ता से बेदखल कर दिया था। अब, देखा यह है कि उनके पौत्र जूनियर एन.टी.आर. प्रत्यक्षः या अप्रत्यक्षतः रूप से राजनीति में कूदते हैं अथवा नहीं। अत्यधिक सफल फिल्म स्टार जूनियर एन.टी.आर. इन दोनों

तेलुगुभाषी राज्यों में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं तथा इस नाते वे एक ऐसे व्यक्ति सिद्ध हो सकते हैं, जो एक ऐसे समय पर भाजपा को आगे बढ़ा सकता है, जब पार्टी के पास वहाँ कोई ऐसा नेता नहीं है, जो वहाँ सुस्थापित राजनेताओं-आन्ध्रप्रदेश में जगमोहन रेड्डी तथा तेलंगाना में के चन्द्रशेखर राव को टक्कर दे सके। राज्य के पूर्व मंत्री तथा वाय. एस.आर.सी.पी. के विधायक कोडाली नानी ने कहा कि यह बिल्कूल साफ है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह फिल्मों के दिवाने इन दोनों तेलुगुभाषी राज्यों में फिल्मी दुनिया के किन्हीं लोकप्रिय नामों की (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

तीस्ता को जमानत?

—जाल खंबाता—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 22 अगस्ता। 2002 के गुजरात दंगों के मामले में निर्दोष लोगों को फँसाने के लिये, कथित रूप से जाली दस्तावेज तैयार करने के मामले गिरफ्तार हुई सोशल ऐक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ को एक्सपार्टी अन्तरिम

- सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ को अंतरिम जमानत देने से इंकार कर दिया, पर उनकी याचिका पर गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया। जमानत देने से इनकार कर दिया साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर दिये, जिनका जवाब गुरुवार को चाहा गया है। बेंच की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने शुक्र में (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

गहलोत अचानक शाम को दिल्ली पहुंचे

ऐसा माना जा रहा है कि, वे संभवतया सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे

—रेणु मिश्रल—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 22 अगस्ता। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से कल मुलाकात करने की खबरों के बीच आज शाम दिल्ली पहुँचे। सूत्र बताते हैं कि राहुल गांधी द्वारा गांधी परिवार से अलग पार्टी के किसी सीनियर नेता, यानी कि अशोक गहलोत को कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव पर सोनिया गांधी गहलोत से चर्चा करना चाहती हैं। सूत्र बताते हैं कि गहलोत किसी भी कीमत पर अपने मुख्यमंत्री पद को कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते और वह सार्वजनिक रूप से यह पहले ही कह चुके हैं कि वे जयपुर नहीं छोड़ना चाहते। गहलोत ने आज फिर इसे लेकर बेबाक बातचीत की कि पार्टी नेता और कार्यकर्ता किस प्रकार से राहुल को कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते

- दोनों की बातचीत में मुख्य मुद्दा होगा, राहुल गांधी का प्रस्ताव कि, गैर गांधी परिवार के व्यक्ति को (गहलोत को) कांग्रेस अध्यक्ष का पद सम्भलवाना चाहिये।
- जैसा कि, विदित ही है, गहलोत राजस्थान के मु.मंत्री की कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते, तथा उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा है कि, वे जयपुर नहीं छोड़ना चाहेंगे।
- कांग्रेस की, संगठन चुनाव की जिम्मेवारी सम्भालने वाली “इलैक्शन अथॉरिटी” ने इस संदर्भ में कहा है कि, चुनाव पूर्व निश्चित व घोषित प्रोग्राम के तहत समय पर ही होंगे।
- पर, जैसा देखा जा रहा है, अथॉरिटी के अधिकार अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने ग्रहण कर लिये हैं और अभी तक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की कोई बैठक निकट भविष्य में प्रस्तावित नहीं है, अतः कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव आगे खिसक भी सकता है।

हैं। राहुल गांधी को उनकी सलाह यह है कि वे इस पद को स्वीकार कर कांग्रेस

लोग निराश होकर घर बैठ जाएंगे, जिससे पार्टी का नुकसान होगा। कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष के मुद्दे को लेकर अनिश्चित है और कुलमिलाकर इस मामले के स्थगित होने की उम्मीद है और यह कुछ समय तक खिंच सकता है। पार्टी के चुनाव प्राधिकरण ने कहा कि चुनाव तय कार्यक्रम अनुसार ही होंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि चुनाव प्राधिकरण की कुछ शक्तियों को कांग्रेस वर्किंग कमेटी (सी.डब्ल्यू.सी.) ने हड़प लिया है, और वही चुनाव कार्यक्रम को अंतिम रूप देगी तथा उसे अनुमोदित करेगी। लेकिन वास्तविकता यह है कि चुनाव का कोई कार्यक्रम नहीं बनाया गया है और सी.डब्ल्यू.सी. की किसी मीटिंग की घोषणा नहीं की गई है। महत्वपूर्ण ये है कि अशोक गहलोत दिल्ली क्यों आए हैं और कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन बनेगा इसके सम्बंध में 10 जनपथ वास्तव में क्या करने जा रहा है।

अध्यक्ष बन जाएँ उन्होंने कहा कि यदि राहुल ऐसा नहीं करते हैं तो कांग्रेस के

खेलों में सरकारी दखल

—जाल खंबाता—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 22 अगस्ता। सरकार यह स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि स्पोर्ट्स की वैश्विक इकाईयों द्वारा भारतीय स्पोर्ट्स इकाईयों के अधिस्वीकरण के निरस्त होने का कारण भारत की सभी स्पोर्ट्स इकाईयों में उसके द्वारा नैशनल स्पोर्ट्स कोड को जबरन लागू करने का प्रयास और उनके क्रियाकलापों में दखलंदाजी करना है।

- सुप्रीम कोर्ट ने खेलों में सरकारी दखल को रोकने के लिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन पर नैशनल स्पोर्ट्स कोड के तहत गठित कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स पर रोक लगा दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस कोड के अधीन दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त तीन सदस्यीय कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स (सी.ओ.ए.) को इण्डियन ओलॉम्पिक एसोसिएशन (आई.ओ.ए.) का कामकाज संभालने से सोमवार को रोक दिया। जस्टिस डी.वाय. चन्द्रचूड और जस्टिस ए.एस. बोपन्ना की एक सुप्रीम कोर्ट बेंच ने 28 अगस्त से शुरू होने जा रहे ए.आई.एफ.एफ. के चुनाव कार्यक्रम (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘मैं राजपूत हूं, सिर कटा सकता हूं, पर साजिश करने वाले भ्रष्ट लोगों के सामने सिर झुका नहीं सकता’

सिसोदिया ने केजरीवाल के साथ गुजरात का चुनावी दौरा करते हुए हिम्मतनगर व भावनगर में कहा

—सुकुमार साह—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 22 अगस्ता। एक कुलीन राजपूत के वास्तविक तेवर दिखाते हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भाजपा को चेतावनी देते हुए कहा कि वह उनके खिलाफ कथित दिल्ली शराब लायसेंस घोटाले में कार्रवाई करके दिखाए। इस घोटाले ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है और आप नेता अरविन्द केजरीवाल व सिसोदिया ने इस मुद्दे को लेकर अपनी ताल ठोक दी है। सिसोदिया ने कहा कि “मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूँ और एक राजपूत हूँ। मैं अपना सिर कटवाने को तैयार हूँ लेकिन षड़यंत्रकारियों और भ्रष्ट

- सिसोदिया ने यह भी कहा कि, उन्हें भाजपा की ओर से संदेश मिला है, अगर वे आम आदमी पार्टी से नाता तोड़ लेते हैं, तो, उनके खिलाफ सी.बी.आई. व ई.डी. की कार्यवाही खत्म कर दी जायेगी।
- सिसोदिया ने अपनी “एकसाइज पॉलिसी” के बारे में कहा कि, यह पॉलिसी अपनी तरह की “सर्वोत्तम पॉलिसी” थी, जिससे दिल्ली सरकार को प्रतिवर्ष दस हजार करोड़ की आमदनी होती। पर, निर्वर्तमान लै. गवर्नर ने अंतिम क्षणों में पॉलिसी से छेड़-छाड़ करके पॉलिसी में परिवर्तन कराये, जिससे सब कुछ बदल गया। उनसे कहा गया है कि “अगर वह आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होते हैं तो उनके खिलाफ लगे सी.बी.आई. और एन्फोर्समेंट

डायरैक्टोरेट (ई.डी.) के केस बंद कर दिए जाएंगे।” सिसोदिया ने ट्वीट किया कि “मुझे भाजपा से संदेश प्राप्त हुआ है। आप छोड़ो- भाजपा में शामिल हो जाएँ।” सी.बी.आई. ने आप पार्टी के सीनियर नेता पर दिल्ली की आबकारी नीति में बदली गई कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार से संबंधित एक केस को लेकर हाल में छाप मारा था। आबकारी नीति को इस वर्ष की शुरुआत में लागू किया गया था और फिर वापस ले लिया गया। प्रकट रूप से अवचलित, सिसोदिया ने गत सप्ताह यह कहकर बात को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया कि दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 अपने आप में सर्वश्रेष्ठ थी और यदि पूर्व